भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

12–13 जून, 2010

पटना (बिहार)

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का संबोधन

आदरणीय आडवाणीजी, मंच पर बैठे अन्य सहयोगियो और साथी प्रतिनिधियो,

मित्रो, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। मैं इस महत्वपूर्ण पार्टी फोरम में सदस्य बनने के लिए आप सभी का अभिनन्दन करता हूं और न केवल इस संगठन की बैठक में होने वाले विमर्श, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना कोई सामान्य बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मिशन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमें अपने को सिद्ध करने का सुअवसर मिला है। जैसाकि मैं अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से बार–बार अपील करता रहा हूं कि हमें स्वचालित इंजन बनने की कोशिश करनी चाहिए। आदेशों और निर्देशों के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार मत कीजिए। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अपने को आम जनता से जोड़िए, उनकी पीड़ाओं और आकांक्षाओं में भागीदार बनिए, उनके बीच काम करिए, अपनी विचार शक्ति के जरिए योगदान करिए, नए विचार दीजिए और पार्टी के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मुखर बनिए। राजनीतिक सक्रियता का चरित्र बदल रहा है। हमें इस बदलाव के अनुरूप अपने को ढ़ालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सशक्त बनेंगे तो पार्टी स्वतः सशक्त बन जाएगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।

बिहार : समृद्ध धरोहर की भूमि

मित्रो, बिहार की राजधानी पटना साहिब में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्राचीन काल से ही बिहार राज्य और पाटलीपुत्र के इस ऐतिहासिक शहर का हमारे इतिहास में गौरवशाली स्थान रहा है। यह महात्मा गौतम बुद्ध की भूमि रही है। चंद्रगुप्त मौर्य और आर्य चाणक्य जैसे कई महान नायक यहीं पैदा हुए थे। यही वह भूमि है जिसने भगवान महावीर, गुरू गोविंद सिंह, मजरूल हक, बाबू कुंवर सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कवि सदानंद सरस्वती, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण और प्रभावतीजी और कर्पूरी ठाकुर सरीखे भारत माता के महान् सपूत–सुपुत्रियों को जन्म दिया। जिन्हें राष्ट्र में सर्वाधिक सम्मान से देखा जाता है। मैं अपनी बात रखने से पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं।

गौतम बुद्ध ने शांति, सद्भाव और त्याग का उपदेश दिया था। भारतीय लोकाचार के निर्माण में इन शिक्षाओं का अपना स्थान है। उन्होंने अपने शिष्यों को परम संदेश दिया था, 'आत्ता दीप भव' जिसका अर्थ है, 'आत्म दीपो भव'। इस संदेश की चिरंतन प्रासंगिकता को

कभी नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी से लेकर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर तक, बुद्ध की शिक्षाओं ने सैकड़ों दार्शनिकों और चिंतकों को प्रभावित किया। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग बौद्धधर्म के अनुयायी हैं। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चम्पारण में गांधीजी का संघर्ष आज भी मेरे हृदय में तरोताजा है। शिक्षा के महान केन्द्र नालंदा और आध्यात्मिक केन्द्र राजगीर बिहार के रत्नों की तरह हैं।

जब हम सब बिहार में हों तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की याद आना स्वाभाविक है। आप में से कइयों की तरह, मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में जेपी से बहुत प्रभावित था, खासकर जब उन्होंने समग्र परिवर्तन के लिए एक जनांदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इमरजेंसी के कठोर शासन से लड़ते हुए लोकतंत्र की बहाली में अपना अमूल्य योगदान किया। इसके लिए राष्ट्र उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। पटना शहर, खासकर ऐतिहासिक गांधी मैदान जेपी, के आह्वान पर आम जनता के विशाल जनसैलाब का साक्षी रहा है।

नानाजी और भैरोंसिंहजी

जेपी और 1974 के आंदोलन के बारे में बात करते हुए स्वर्गीय नानाजी देशमुख का स्मरण आना स्वाभाविक है। नानाजी ने यहीं पुलिस लाठीचार्ज का सामना करते हुए जेपी की रक्षा की थी। नानाजी के दुःखद निधन से इस राष्ट्र और भाजपा के हम कार्यकर्ताओं ने एक महान् नेता को खो दिया। नानाजी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जो कहते थे, उस पर चलने का साहस दिखाते थे। उन्होंने हमें दिखाया कि साठ की उम्र पार कर जाने के बाद भी दलीय राजनीति से ऊपर उठते हुए किस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान किया जा सकता है। चित्रकूट में उन्होंने ग्रामीण उत्थान के लिए असंख्य और अत्यंत सफल प्रयोग किए। विकसित भारत के निर्माण के लिए कुछ ठोस करने के इच्छुक हजारों युवक इन प्रयोगों से प्रेरणा लेते रहेंगे। नानाजी ने अपने रचनाकर्म के जरिए यह दिखाया कि जब हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता से काम करता है तो आशा से अधिक काम भी कर सकता है। भारत के इस आधुनिक ऋषि को मैं नमन करता हूं।

कुछ हफ्ते पहले, हमने अपने वरिष्ठ नेताओं में एक भैरोंसिंह शेखावत को भी खो दिया। आधुनिक राजस्थान के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे सही मायने में राजनेता थे। मुख्यमंत्री से लेकर उप–राष्ट्रपति तक वे जिस किसी भी पद पर रहे, उन्होंने उसे गरिमा प्रदान की। जनसंघ के दिनों में, भूमि सुधार के मुद्दे पर पार्टी के एक बड़े तबके के कड़े विरोध के बावजूद वे पार्टी के निर्देशों पर अटल रहे। उनके लिए पार्टी और विचारधारा सर्वोपरि थी। दोनों दिवंगत नेताओं को नमन करते हुए, मैं अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों पर चलने की मिसाल पेश करें।

प्रगति पथ पर बिहार

मित्रो, आज हम बिहार में हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बिहार में पहली बार कोई सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है और वांछित परिणाम दे रही है। बिहार के पिछले शासकों ने राज्य के लोगों में शर्मिंदगी और हीनभावना पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया में कई लोग बिहार को केवल 'बीमारू' के पहले अक्षर के रूप में

जानते थे। एनडीए शासन में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बीमारू बिहार 'जुझारू' बिहार में परिवर्तित हो गया है। मैं यहां के एनडीए नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जिसने हर बिहारी में गर्व की भावना भर दी है। बिहार ने 11 प्रतिशत की आश्चर्यजनक विकास दर हासिल कर एक मिसाल कायम की है। मैं राज्य के उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी और कैबिनेट में उनके सभी सहयोगियों को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में यह चमत्कार कर दिखाया है। याद रखिए, कुशासन ने बिहार की नकारात्मक विकास दर को 5 से 15 प्रतिशत के बीच पहुंचा दिया था जहां से एनडीए उसे सकारात्मक 11 प्रतिशत पर ले आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार के लोग एक बार फिर एनडीए में अपना भरोसा जताएंगे, राज्य को सफलता की बुलंदी पर पहुंचाएंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम रोशन करेंगे।

यूपीए : कुशासन का वर्ष

मित्रो, यूपीए–2 ने सत्ता में एक वर्ष पूरा कर लिया है। लेकिन उसका यह पहला वर्ष विफलताओं के नाम है। इस पृष्ठभूमि में इस निष्क्रियता के वर्ष पर विचार करना समीचीन होगा। जहां रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करने जैसा काम स्वागतयोग्य है, वहीं यह भी सच है कि प्रतिभाशाली छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन केवल रिपोर्ट कार्ड के जरिए नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी करता है। कांग्रेस ने 1०० दिनों में जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन कीमतें शत–प्रतिशत बढ़ गईं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे विकास दर को दो अंकों में पहुंचा देंगे। विकास दर दो अंकों में तो नहीं पहुंची, लेकिन मुद्रास्फीति दो अंकों में जरूर पहुंच गई।

कमोडिटी एक्सचेंज में फॉरवर्ड ट्रेडिंग से केवल ०.3 प्रतिशत वास्तविक डिलिवरी हुई और 99.7 प्रतिशत कारोबार अटकल तथा जोड़तोड़ में खत्म हुआ। बिचौलियों और जमाखोरों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूँ, चीनी, कपास, तेल और कई अन्य वस्तुओं का कृत्रिम तरीके से अभाव पैदा किया गया। हमने मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं को कमोडिटी एक्सचेंज के दायरे से बाहर कर दिया जाए। लेकिन यूपीए ने अभी तक हमारी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यथास्थिति बनाए रखने में उसके कुछ निहित स्वार्थ हैं।

यह कुशासन का वर्ष था। इसके पहले कांग्रेस अपनी सामूहिक विफलता के लिए यूपीए के पिछले घटकों–खासतौर पर कम्युनिस्टों–को दोषी ठहराया करती थी। आज कांग्रेस अपनी विफलताओं के लिए किसी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकती। एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विपरीत, यूपीए के राजनीतिक नेतृत्व के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वह अपने घटक दलों के मंत्रियों से–चाहे वे कृषि मंत्री हों, नागरिक उड्डयन मंत्री हों, संचार मंत्री हों या रेल मंत्री हों–जवाबतलबी कर सकें। इस 'अनस्क्रूपलस प्रोटेक्शन एलायंस' (सिद्धांतहीनता संरक्षण गठबंधन) के घटकों के बीच एक अलिखित समझौता दिखता है–'हम जवाब नहीं मांगेंगे, तुम सवाल मत पूछो।'

यूपीए–2 की शुरुआत तेलंगाना के बारे में राजनीतिक फैसले के अभाव से हुई। बाद में और भी कई विफलताएं सामने आईं। यूपीए सरकार निम्न क्षेत्रों में विफल रही–

- नक्सली खतरे से निपटने के लिए एक सुसंगत रणनीति बनाने में

- लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने में
- मणिपुर की स्थिति की गंभीरता को समझने में
- अमेरिका से अपनी शर्तों पर बात करने में
- पाकिस्तान के साथ आवश्यक दृढ़ता दिखाने में
- बढ़ती कीमतों के खिलाफ बाजार पर अंकुश लगाने में
- गांवों और नगरों में गरीबों का शोषण करने से बाजार को रोकने में
- भारत के गरीबों की वास्तविक संख्या बताने में।

कुल मिलाकर यूपीए–2 का पहला साल सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। यह कुशासन दूसरी चीजों के साथ–साथ इस सरकार की कुछ बुनियादी विसंगतियों का परिणाम है। यूपीए शासन की सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि उसके प्रशासनिक नेतृत्व में राजनीतिक क्षमता का अभाव है और पीठासीन राजनीतिक मूर्ति को शासन की जटिलताओं की समझ नहीं है। इससे भारत की जनता की स्थिति बदतर हो गई है और इन गड़बड़ियों को परामर्श का कोई भी तंत्र दूर नहीं कर सकता। सरकार की ईमानदारी और इरादे पूर्णतया संदेहास्पद हैं।

ब्रिटेन में चुनाव

मित्रो, भाजपा की तरफ से मैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री डेविड केमरन को बधाई देता हूं और कंजरवेटिव–लिबरल सरकार के गठन का स्वागत करता हूं। यह सुखद है कि नई सरकार ''भारत के साथ और ज्यादा भागीदारी'' के लिए प्रतिबद्ध है। यह भागीदारी 21वीं शताब्दी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नए भारत और एक नए ब्रिटेन के बीच होनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि इन ताजा ब्रिटिश संसदीय चुनावों ने 'फर्स्ट–पास्ट–द–पोस्ट' चुनावी प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। भाजपा काफी लम्बे समय से हमारी चुनावी प्रणाली में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय बहस की बात मुखर करती रही है ताकि खण्डित जनादेश की कठिनाइयों या एक ऐसे जनादेश जो राष्ट्रीय मूड या अधिसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त न करता हो, को टाला जा सके। शायद यह इस बहस को पुनः शुरू करने का आधार बन सके।

हमारे पड़ोस में स्थिति

नेपाल में स्थिति अभी भी डॉवाडोल है। हम अपने इस परंपरागत पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता की कामना करते हैं। यह हिमालयी राष्ट्र एक बार फिर राजनीतिक कलह और तनाव से ग्रस्त है। ऐसे में हम भारत सरकार से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए हर तरह की मदद करने की अपील करते हैं। भारत सरकार को माओवादियों द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों के प्रति सचेत रहना चाहिए जैसाकि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर से भारतीय पुजारियों को निकालने के समय किया। हम माओवादी कॉडर को सिविल समाज से जोड़ने के प्रयासों और हाल में जनता के साथ हुए अन्याय को दूर करने संबंधी प्रशासनिक तथा अन्य उपायों का भी स्वागत करते हैं। इस समूचे क्षेत्र की जनता के हित में यही है कि हिंसा में विश्वास करनेवाले लोगों के वर्चस्व को खत्म किया जाए और कानून व्यवस्था तथा शासन को और सुदृढ़ बनाया जाए।

पाकिस्तान में स्थिति सामान्य से कोसों दूर है। पाकिस्तान सरकार की कथनी और करनी में अंतर बना हुआ है। दुर्भाग्य से, भारत सरकार भी पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देने में विफल रही है कि यदि वह आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देता रहेगा तो उसे उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सरकार में दृढ़ निश्चय के साहस के संकट ने भारत–पाक संबंधों के सारे पहलुओं में जटिलता ला दी हैं। हमारे अड़ियल पड़ोसी के लिए हमारी अधिकृत चेतावनी खोखली साबित हुई है क्योंकि इसमें स्पष्टता का अभाव है। यह देखकर निराशा होती है कि पाकिस्तान में फर्जी न्याय प्रक्रिया और आतंक के आकाओं को दण्डित करने में उनकी असफलता पर भारत सरकार की दबी प्रतिक्रिया के चलते हमारे प्रधानमंत्री वार्ता के लिए प्रोत्साहित हो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके गृहमंत्री बातचीत के विरुद्ध बोलते हैं। हम भाजपा वालों का मानना है कि पाक से बातचीत तब तक निरर्थक रहेगी जब तक वह अपनी भूमि से आतंकी नेटवर्क को समाप्त नहीं कर देता। हमारी यह धारणा बलवती होती जा रही है कि हमारे कूटनीतिज्ञ पाकिस्तान से बात तो करते हैं, लेकिन वह केवल अपने मतलब की बातें ही सुनता है। आतंक को तनिक भी बर्दाश्त न करने पर हमारी स्थिति भ्रम के चलते कमजोर हुई है। इससे सीमाओं पर रक्षा करने वालों और अर्द्ध–सैन्य बलों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।

श्रीलंका ने आतंकवादियों को परास्त कर शांति पाने में सफलता पाई है लेकिन उन्हें अब आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों का दिल जीतना है। हमारी नेता और लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे के सामने हमारे स्थिति स्पष्ट की है। हम मांग करते हैः आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को सम्मान और आदर के साथ अच्छे से पुनर्वासित किया जाए। श्रीलंकाई संविधान के तेरहवें संशोधन से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तीसरा और महत्वपूर्ण कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय सुरक्षा चिंताओं को श्रीलंका सम्मान दे।

इसी तरह, चीन के प्रति हमारा रवैया भ्रांति को बढ़ाने का रहा है। हाल में भारतीय राष्ट्रपति की चीन यात्रा के दौरान, भारत से चीन की अखंडता का समर्थन करवाया गया। लेकिन भारतीय पक्ष चीन से यह कहलवाने में विफल रहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले जो यह आशंका प्रकट करते है कि भारत सरकार सिर्फ प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति का अनुसरण करती है। परन्तु यह स्थिति बदलनी चाहिए।

भारत–अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी

भारत–अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर काफी कुछ कहा गया है। भाजपा ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करती हैं जिससे परस्पर हितों की रक्षा और एक–दूसरे की चिंताओं को समझने के आधार पर रिश्ते मजबूत होते हों। जबकि हम यह मानते हैं कि परस्पर हितों और समानता पर आधारित भारत–अमेरिका रणनीतिक संबंधों से काफी लाभ हो सकता है, उसी समय ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अमेरिका की बंधक बनी हुई है। वास्तव में, भारत–अमेरिकी सम्बन्ध अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को बढ़ाने, इसी तरह अफगानिस्तान में पाकिस्तान हितों को बढ़ाने का आवरण बने हैं; इसके अलावा इस्लामाबाद की अनर्गल मांगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत–अमेरिकी संबंधों को परस्पर हितों और भारत के

रणनीतिक हितों के नए स्तर पर ले जाने में सफलता पाई थी। एनडीए सरकार के समय हुए लाभों को यूपीए की दब्बू सरकार ने यूं ही खो दिया, जोकि अमेरिका से बदले में समान लाभों को पाए बगैर झुकने को तैयार है। उदाहरण के लिए, परमाणु दायित्व विधेयक के प्रारूप को देखकर हैरानी होती है कि कैसे उसमें हमारे राष्ट्रीय हितों को ताक में रखकर अमेरिकी व्यवसायियों के हितों की रक्षा की गई है; उससे ज्यादा यह शोचनीय है कि इसमें भारतीय जीवन की कीमत को सस्ते दामों में आंका गया है।

साथ ही हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि भारत के लोग कभी भी अमेरिका से ऐसे सौदे या समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, लचीलेपन और इसकी विदेश नीति में कूटनीतिक जोड़तोड़ की गुंजाइश को तिलांजलि दे दी जाए।

भोपाल गैस त्रासदी पर फैसला

यहां यह दोहराना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भाजपा परमाणु दायित्व विधेयक का कड़ा विरोध करती है। भोपाल गैस त्रासदी पर हाल के फैसले के बाद, इस तरह के कानून का खतरा और स्पष्ट हो गया है। सीबीआई के पूर्व अधिकारी बी.आर. लाल ने रहस्योद्घाटन किया कि किस तरह तत्कालीन केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड प्रबंधन, खासतौर पर कंपनी के भगोड़े सीईओ वारेन ऐंडरसन को बचाने की कोशिश की थी। यह इस बात की ताजा मिसाल है कि किस तरह रात–दिन आम आदमी की कसम खानेवाले लोग उसी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी का फैसला हमारी न्यायिक प्रणाली द्वारा किया गया क्रूर मजाक है। भाजपा मांग करती है कि सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे। भोपाल इस बात की मिसाल है कि किस तरह हमारी न्यायिक प्रणाली की अंतर्निहित कमजोरी के कारण दोषी बरी हो जाते हैं। भोपाल ने एक बार फिर समूचे राष्ट्र के सम्मुख दोहराया है कि कैसे कांग्रेसी शासक समय–समय पर अपने निजी और राजनीतिक हितों के लिए, लोगों के हितों से समझौता करते रहे हैं।

आतंकवाद

आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कानूनी भाषा में कहें तो कसाब की किस्मत के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अफजल गुरु को फाँसी पर लटकाने में हो रही देरी के बारे में नए रहस्योद्घाटन यूपीए सरकार की घुटने टेकने वाली नीति को ही साबित करते हैं। पूर्व गृहमंत्री द्वारा इस मामले में डाली गई बाधाओं के बारे में कुछ नई सच्चाईयां सामने आई हैं। इस आलोक में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को बार–बार दी गई गलत सूचनाओं के बारे में सफाई दें। विडंबना तो यह है कि यूपीए सरकार अफजल गुरु को फाँसी पर लटकाए जाने के बाद की कानून–व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित दिखती है, न कि सींखचों के पीछे उसे रखे जाने के कारणों के बारे में। यह ऐसी सरकार है, जो कानून का पालन करनेवाले लोगों के जीवन की बजाय हमारे खिलाफ युद्ध छेड़नेवाले एक खतरनाक अपराधी की मौत के बारे में अधिक चिंतित है!

नक्सली खतरा

इसके अलावा, हम सभी के सामने नक्सली खतरा भी गंभीर बना हुआ है। भाजपा ने बार–बार कहा है कि यदि सरकार नक्सली खतरे से निपटने के लिए कारगर कदम उठाती है तो पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन सरकार भ्रम और उलझन में दिखती है। आंतरिक सुरक्षा के प्रतिष्ठान इस खतरे को समझने में विफल दिखते हैं। हालांकि अल्प–विकसित क्षेत्रों में, खासकर जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास की जरूरत है; लेकिन यह नक्सली खतरे के खत्म हो जाने की गारंटी नहीं है। जहां नक्सली राज्य सरकारों की सत्ता को खुली चुनौती देते रहे हैं या दे रहे हैं, वहीं यूपीए सरकार के कुछ मंत्री उनसे सहानुभूति दिखा रहे हैं। दृष्टिकोण में यह दुविधा गलत संदेश दे रही है। एक ओर जहां इन कदमों से पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का मनोबल गिर रहा है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। मैं यूपीए को चेतावनी देता हूं कि वह नक्सलियों और उनकी हिंसा के शिकार लोगों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाकर आग से खेल रही है। इस संदर्भ में सरकार के रवैए से इस मुद्दे पर गंभीरता का अभाव दिखता है।

हम दंतेवाड़ा में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या और मिदनापुर जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर हमले से भी विशेष रूप से चिंतित हैं। दुर्भाग्य से मानवाधिकारों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पैरोकार उस समय खामोश रहते हैं, जब नक्सली सैकड़ों निर्दोष लोगों के जीने के बुनियादी अधिकार का हनन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने में पक्षपात न करें। नक्सलियों की क्रूरता और घोर अनाचार–अन्याय के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मैं अपनी राज्य इकाइयों से उन जगहों पर *'जन–सुनवाई'* सरीखे कार्यक्रम आयोजित करने की अपील करता हूं, जहां नक्सली बर्बरता के शिकार लोग जनता के साथ अपनी पीड़ा बांट सकें। नक्सलियों को प्रबुद्ध वर्ग और समाज के कुछ तबकों में इसलिए समर्थन हासिल है, क्योंकि ये तबके आम तौर पर नक्सली गतिविधियों के इन पहलुओं से अनजान हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आम जनता को इस बारे में बताएं।

दलितों से कांग्रेसी विश्वासघात

हाल ही में हरियाणा में हुए सामाजिक झगड़ों की घटनाएं चिंताजनक हैं। मिर्चीपुर में हुई घटनाएं अत्यधिक निंदनीय हैं। वहां के पीड़ित अभी भी दिल्ली में भय के साये में रह रहे हैं। हरियाणा की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील बनी हुई है और प्रभावित परिवारों को उनके घरों को लौटने में आश्वस्त करने में भी असफल हुई है।

सी.बी.आई.–कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्टिमिडेशन

जब राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा की अनेकविध खतरों का सामना कर रहा है तब सरकार सी.बी.आई. को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करने को बाध्य कर रही है। सी.बी.आई. डराने का हथियार बन गई है। भोपाल त्रासदी के संदर्भ में इसके एक अधिकारी द्वारा किए गए ताजे रहस्योद्घाटन ने हमारे इस भय की पुष्टि की है कि कांग्रेस इस रणनीति को अपनाकर अपने विरोधियों को झुकाती है या कानून से अपने परिचितों– क्वातरोची और एंडरसन को कानून की पकड़ से आजाद कराती है। इससे सिद्ध होता है कि

उनकी प्रतिबद्धता भारत के लोगों के प्रति नहीं हैं। भाजपा सी.बी.आई. के दुरुपयोग की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की जोरदार मांग करती हैं।

कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा

कांग्रेस शासन में कृषि की उपेक्षा का लम्बा इतिहास रहा है। कृषि, पानी और ग्रामीण विकास उसके लिए नारेबाजी तक सीमित रहे हैं। एक और किसानों को उनके उत्पादों के पर्याप्त दाम नहीं दिए गए तो दूसरी और उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम देने पड़ते हैं। हाल ही में कांग्रेस शासित प्रदेशों और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद समय पर नहीं हो पाई, अतः नतीजा यह हुआ कि किसानों को उनकी नई फसल को बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों में पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के अभाव ने इसे और बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण बाजार हस्तक्षेप रणनीति का भी अभाव रहा। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बाजार में जब भी नई फसल आए तो वे सार्वजनिक खरीदी केंद्रों पर जाएं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि किसान को बगैर भ्रष्टाचार और परेशानी के उनको उनका हक मिले।

प्रधानमंत्री अक्सर हरित क्रांति की बात करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने की न तो उन्होंने कोई इच्छा दिखाई है और न ही कोई ब्लूप्रिंट सामने रखा है। कृषि मंत्री ने स्वीकारा है कि 58,000 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न प्रति वर्ष सड़ जाता है। मैं कृषि विकास के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। पानी कृषि विकास की कुंजी है। भाजपा मांग करती है कि सिंचाई को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि बाढ़ और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भारत में यह दयनीय है कि किसानों को अच्छी किस्म का बीज आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ कुछ दिन पहले ही जोधपुर में किसानों को लाठियां इसलिए सहनी पड़ीं क्योंकि वे अच्छी किस्म के बीजों की मांग कर रहे थे। सरकार को कृषि वित्त जैसे मुद्दों की बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं आपका आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में हमने समग्र कृषि विकास रणनीति बनाई है जिसके चलते गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ तथा अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में अच्छे नतीजे सामने आए हैं।

मणिपुर की स्थिति

आप सभी लोगों की तरह मैं भी मणिपुर की स्थिति से बहुत चिंतित हूं। पिछले 7० दिनों से मणिपुर की सड़कें बंद हैं और वहां रह रहे हमारे बंधुओं का जीना दूभर हो गया है। मणिपुर सरकार ने मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (एडीसी) के चुनाव कराने का फैसला किया था। इसके विरोध में नगा छात्र संगठनों और कुछ नगा राष्ट्रवादी सिविल सोसाइटी संगठनों ने 11 अप्रैल से मणिपुर जानेवाली सड़कें अवरुद्ध कर दीं। हमारा मानना है कि नगा नेता थुइंगलेंग मुवैया ने पहले मणिपुर में अपने गांव जाने का ऐलान कर और फिर बाद में सड़कों को अवरुद्ध करने की राजनीति में शामिल होकर खतरनाक खेल खेला है। यह बेहद खेदजनक है कि नगा समूहों को समूचे मणिपुर राज्य को बंधक बनाने की छूट दे दी गई है और केंद्र सरकार मूक–दर्शक बनी हुई मणिपुर के लोगों की दयनीय स्थिति को चुपचाप देख रही है। जहां नगाओं की समुचित मांगों पर निश्चित रूप से ध्यान

दिया जाना चाहिए, वहीं लोकतांत्रिक राज्यतंत्र में अवरोध की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

हम पूरी तरह मणिपुर की जनता के साथ हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वह उनके साथ उसी तरह की संवेदनशीलता दिखाए, जिस तरह की संवेदनशीलता वह कश्मीर घाटी की जनता के साथ दिखाती है। भाजपा केंद्र सरकार से यह भी मांग करती है कि वह वैकल्पिक सड़कें खोलने और हवाई जहाज से खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं गिराने जैसी कार्रवाई कर यह स्पष्ट संदेश दे कि राष्ट्र की सहानुभूति मणिपुर की जनता के साथ है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री को इंफाल जाकर अपनी सरकार और राष्ट्र के दूसरे हिस्सों की जनता की ओर से चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने स्थिति को और अधिक बिगड़ने दिया तो दोनों राज्यों के अलगाववादी नेता जनता के गुस्से को पूरी तरह भुनाएंगे जिससे अशांति तथा हिंसा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैं महानगरों में रहनेवाले अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से खासतौर पर अपील करता हूं कि वे अपने शहर में मणिपुरी विद्यार्थियों और युवाओं से मिलें और उन्हें बताएं कि देश के दूसरे हिस्सों की जनता उनके साथ है। भाजपा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून को 'मणिपुर एकता दिवस' के रूप में मनाएगी, सभी राज्यों की राजधानियों में हमारे कार्यकर्ता उस दिन उपवास करेंगे और एकदिवसीय धरना देंगे।

महंगाई के विरुद्ध लड़ाई

मित्रो, मुझे खुशी है कि 21 अप्रैल को संसद् तक मार्च कर हमने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर जनता को संगठित किया था और उसकी पीड़ा को सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति दी थी। आसमान छूती महंगाई ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने यह काम कई तरीकों से किया। हमने लोगों को बताया कि यह महंगाई गलत आर्थिक नीतियों और वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। हमने यह भी साबित किया कि सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए लाखों टन गेहूं सड़ने दिया गया। हम आलू उत्पादकों की दयनीय स्थिति को भी सफलतापूर्वक सामने लाए। लेकिन दुर्भाग्य से यह सरकार लोगों की परेशानियों के प्रति इतनी उदासीन है कि उसने उनकी तंगहाली में और भी इजाफा कर दिया। हाल में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी घाव पर नमक छिड़कने की दूसरी मिसाल है। याद रहे जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो कीमतें सदैव आकाश छूने लगती हैं। भाजपा कीमतों में इस बढ़ोतरी की निंदा करती है और यूपीए को चेतावनी देती है कि महंगाई के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा उसकी सरकार के जनादेश को जल्दी ही जलाकर खाक कर देगा।

इस मौके पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि कीमतों में वृद्धि के खिलाफ हमारा राष्ट्रीय अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। महंगाई के विरुद्ध हमारे ज्ञापन पर इकट्ठे किए गए करोड़ों हस्ताक्षर हम संसद् के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति को सौंपेंगे।

सुराज संकल्प

अब मैं अन्य कुछ मोर्चों पर पार्टी की नई पहलों और प्रगति की चर्चा करूंगा। इंदौर में हमने सुशासन पर और बल देने पर जोर दिया था। भाजपा देश की पहली पार्टी है, जिसने

एक सुशासन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ का काम बेहतर कामकाज के लिए हमारी सरकारों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराना है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर इस प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हाल में इस प्रकोष्ठ ने मुंबई में सफलतापूर्वक 'सुराज संकल्प सम्मेलन' का आयोजन किया। इस सभा में हमने जनोन्मुखी और सुशासन का फिर संकल्प लिया। भाजपा के आठ राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों एवं उप–मुख्यमंत्रियों, 6० मंत्रियों और केंद्र तथा प्रदेशों के कुछ वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में आयोजित इस दो–दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। यह अपने तरह का पहला सम्मेलन था, जिसमें लिया गया सुराज संकल्प यह दर्शाता है कि हम औरों से भिन्न शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि इस सभा से कई दिन पहले एक अग्रणी टीवी चैनल ने देश के सर्वोत्तम पांच मुख्यमंत्रियों में भाजपा के तीन मुख्यमंत्रियों को शामिल किया था। मैं सभी भाजपा सरकारों को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और सुराज संकल्प के क्रियान्वयन में उनकी सफलता की कामना करता हूं। यहां मैं उन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करना चाहता हूं जो हमारे शासित राज्यों में हासिल की गई हैं। देश में कृषि वृद्धि 2% है। बिहार ने कृषि वृद्धि में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर देश को सुखद रूप से चकित कर दिया है। 2002 से 2009 के बीच गुजरात में कृषि वृद्धि 9.6% लगातार बनी रही है। कर्नाटक ने सफलतापूर्वक ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन आयोजित किया जिसने राज्य के प्रति निवेशकों का ध्यान आकृष्ट किया है। पर्यावरण चेतना के युग में हमारी हिमाचल सरकार ने अनेक कदम उठाते हुए कार्बन प्वाइंट हासिल किए हैं जो उनके प्रभावी प्रबंधन को प्रमाणित करते हैं। छत्तीसगढ़ ने तकनीक का प्रभावी रूप से प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इतना प्रामाणिक बनाया है कि यह कुशलता का पर्याय बनी है।

हमारा मानना है कि सुशासन केवल सार्वजनिक प्रशासन तक सीमित नहीं होता। यह हमारे पार्टी मामलों के प्रबंध में भी सहायक होता है। इसके लिए हमें अपने मानव संसाधन विकास प्रक्रिया को सक्रिय करना होगा। इस दिशा में हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने पहले ही पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया है। इस बैठक में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के अब तक के कार्यों और भावी योजनाओं के बारे में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रकोष्ठ जुलाई 2010 से पार्टी कैडर के लिए एक तीन वर्षीय सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। चालू वर्ष में 10,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रकोष्ठ विजयादशमी से ई–टेनिंग की भी शुरूआत करेगा। इसी तरह अंत्योदय के मोर्चे पर हमने एक विनम्र शुरुआत की है। समाज–सेवा को राजनीतिक कार्यों से जोड़ने की यह हमारी अनूठी पहल है। इसके अतिरिक्त, पार्टी के गैर–सदस्य शुभेच्छुओं के लिए बनाए गए मंच 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। इस सत्र में अंत्योदय और 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' पर रिपोर्टें पेश की जाएंगी। इसके अलावा हमने जीएसटी के मुद्दे पर अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। भाजपा शासित राज्यों के सभी जनजाति मामलों के मंत्रियों की बैठक के बाद गठित जनजाति मामलों हेतु एक विशेष समिति की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री भगतसिंह कोशियारी के नेतृत्व में गठित एक समिति ने उत्तर क्षेत्र की हमारी सीमा सुरक्षा के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की है, वह भी यहां प्रस्तुत की जाएगी।

मित्रो, पार्टी की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद पिछले छह महीनों में मैंने चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ और गुवाहाटी से लेकर गोवा तक पूरे देश का दौरा किया है। मैं न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिला हूं, बल्कि कई अभिमत निर्माण करने वालों और प्रमुख नागरिकों से भी मैंने संवाद किया है। भाजपा के लिए हर जगह शुभेच्छा व्यक्त की जा रही है। समाज के हर वर्ग में हमारे समर्थक हैं। करोड़ों देशवासियों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं, भाजपा अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखे। छिद्रान्वेषी होना आसान है। जो लोग दूसरों से भिन्न होने का अपना प्रयास छोड़ देते हैं, उनमें आत्मबल और साहस का अभाव होता है। हम सभी आशावादी हैं, लेकिन हमारी आशावादिता महज खोखली नहीं होनी चाहिए। हमें अपने पथ का निर्माण करना होगा, ताकि भाजपा अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा कर सके। लगभग 35 वर्ष पहले दिल्ली ने 'सिंहासन खाली करो कि जनता आई है' का नारा सुना था। हालांकि यह नारा दिल्ली में गूंजा था, लेकिन उसकी उत्पत्ति पटना में जेपी आंदोलन से हुई थी। पैंतीस साल के बाद, यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम एक भिन्न किस्म की इमरजेंसी पाएंगे, जिससे केंद्र में कुशासन पैदा हुआ है। एक बार फिर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और यूपीए सरकार को चेतावनी देनी होगी कि या तो अच्छा शासन दो या फिर गद्दी छोड़ दो। हमें इस लंबे संघर्ष के लिए अपने को तैयार रखना होगा।

बिहार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जहां राजनीतिक इच्छाशक्ति हो वहां अच्छा कर दिखाने की संभावना रहती है—एनडीए शासन के दौरान बिहार का चहुंमुखी विकास ऐतिहासिक, बेमिसाल और चमत्कारपूर्ण है। यह अनुकरणीय है। एक सुखी और समृद्ध भारत के लिए हमें सुराज और सुशासन की जरूरत है। जिन राज्यों में, हम सत्ता में हैं वहां हमने साबित किया है कि हम इन लक्ष्यों के लिए सक्रिय है। हम लोगों को बताएंगे कि कैसे कांग्रेस *विनाश* करती है जबकि भाजपा *विकास* लाती है।

भारत माता की जय

———